

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936

No. 101]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAITRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15-3/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट-III.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956) (3-1956) की धारा (ग) के उप-अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 28 में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम सृजन करता है, नामतः :-

- (1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों-I एवं II के अंतर्गत रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा:-

"सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) (माह)..... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त'

उपमन्यु बसु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

पाद टिप्पणी:- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2009 में प्रकाशित किया गया था।

अनुलग्नक—I

छात्र का आरवासन

1. मैं (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/..... श्री/श्रीमती/सुश्री जिसे में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित हैं।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आरवासन देता/देती हूँ कि.....
 (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।
 (ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको बढ़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है—और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया दिन..... माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम:

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिभावक, जिसके छात्र को (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस ज्ञात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि.....
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।
(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा-तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./मो. नं.:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अर्थार्थ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th December, 2013

No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

- (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-I

UNDERTAKING BY THE STUDENT

I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. , having been admitted to (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

- (5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- (6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (place) on this the _____ (day) of _____ (month), _____ (year).

Signature of deponent
Name:

ANNEXURE-II

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, (full name of student with admission / registration/enrolment number) _____, having been admitted to _____ (name of the Institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations."

- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
- (a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- (b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- (5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

1431 G/14-2

- (6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) on this the (day) of (month) (year).

Signature of deponent

Name:

UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN

BAHADURSHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI – 110 002

UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.

(Under Section 26 (1) (g) of the University Grants Commission Act, 1956)

Dated June, 2009.

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it

3 Under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.-?

a. Ragging constitutes one or more of any of the following acts: a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;

b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;

c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;

- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student ;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

4. Definitions. -

1) In these regulations unless the context otherwise requires,- a) “Act” means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); b) “Academic year” means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year. c) “Anti-Ragging Helpline” means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations. d) “Commission” means the University Grants Commission; e) “Council” means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils. f) “District Level Anti-Ragging Committee” means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district. g) “Head of the institution” means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred. h) “Fresher” means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution. i) “Institution” means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such

institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma. j) “NAAC” means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act; k) “State Level Monitoring Cell” means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1887, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1887, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration

of students; namely, a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audiovisual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full. Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus. Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.

f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioral pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.

h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent

ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

- i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
- k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.
- m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.
- n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.
- o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.
- p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.

b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the institution in earlier years.

c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.

d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.

e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely;
(i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations;
(ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti -ragging committee;(iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members ; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration.(v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.

f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.

g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such

informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.

j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.

l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.

m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.

n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organization authorized to do so.

o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same.; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.

p) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution. Such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

q) The database shall be made available by Commission to the non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance to the Councils and to such bodies as may be authorized by the Commission or by the Central Government.

r) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.

b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti- Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of

the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counseling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.

b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a

mobile phone by the institution, the number of which shall be publicized among all students residing in the hostel.

c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.

d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.

e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.

f) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes, but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

g) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.

h) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

i) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

j) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

k) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and crosscheck whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

l) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

m) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members or bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

n) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

o) The Vice Chancellor of each University shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.-

On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorized by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;

- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of “Ragging”.

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.-

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;

- a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.
- b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
- c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.
- d) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti- Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
- e) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.
- f) The Commission and respective council shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution through an agency approved by the Ministry of Human Resource Development, Government of India; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.
- g) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorized by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;

- a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.

b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.

c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission that the institution has complied with the anti-ragging measures.

d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorized accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.

e) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.

f) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. Administrative action in the event of ragging.-

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed herein under:

a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.

b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;

i. Suspension from attending classes and academic privileges.

ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.

iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.

- iv. Withholding results.
- v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- vi. Suspension/ expulsion from the hostel.
- vii. Cancellation of admission.
- viii. Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters.
- ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.
- x. Fine which may extend up to Rs.2.5 Lakh. Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;

ii. in case of an order of a University, to its Chancellor.

iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.

ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University. Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.

iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any

iv. Withholding any grants canalized through the university to the institution.

v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental enquiry, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff. Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such action.

9.5 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one or more of the following measures, namely;

- i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.
- ii. Withholding any grant allocated.
- iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.
- iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
- v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations. Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (*full name of parent/guardian*) father/mother/guardian of _____, _____ (*full name of student with admission/registration/enrolment number*) _____, having been admitted to _____ (*name of the institution*), have received a copy of the UGC

Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____ (*full name of student with admission/registration/enrolment number*)
s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____, having
been admitted to _____ (*name of the institution*), have
received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher
Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and
fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to
what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and
am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against
me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part
of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as
ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of
commission or omission that may be constituted as ragging under clause
3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment
according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action
that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in
force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in
any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part
of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is
found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no
part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month),
(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-15/2009(एआरसी) भाग-III

दिनांक : 27 जून, 2019

आदरणीय महोदय/महोदया,

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर दिनांक 08 मई, 2009 की सिविल अपील संख्या 887/2009 में दिए गए निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विनियम, 2009" को अधिसूचित किया है। यह विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। यह विनियम देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य हैं।

चूंकि रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए, बहु प्रणालियों की आवश्यकता है, आपके क्षेत्राधिकार के तहत आपके सम्मानित विश्वविद्यालय तथा सभी संस्थानों में लागू किए जाने वाली कुछ सिफारिशों तथा कार्रवाईयों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

क. मूलभूत उपाय:

1. रैगिंग रोधी समितियों, रैगिंग रोधी दस्तों का गठन, रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना और विभिन्न मीडिया के माध्यम से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्थान की विवरणिका और सूचना पुस्तिकाओं/ ब्रोशर में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाएगा।
3. रैगिंग रोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते और संपर्क संबंधी ब्योरे के साथ संस्थानों की वेबसाइट अद्यतन करना।
4. प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों तथा इसके द्वितीय संशोधन के अनुपालन में प्रत्येक शिक्षा वर्ष में एक ऑनलाइन वचनपत्र जमा करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत को शामिल करते हुए रैगिंग की परिभाषा को विस्तार देने के लिए दिनांक 29 जून, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में तीसरे संशोधन को अधिसूचित किया:

"3. किसी दूसरे छात्र (नए अथवा अन्यथा) पर रंग, नस्ल, धर्म, जाति, नृजातीय, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), यौन झुकाव, रूपरंग, राष्ट्रियता, क्षेत्रीयता, भाषायी पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक दुर्व्यवहार (जिसमें दबंगई तथा बहिष्करण शामिल हैं) का कोई भी कृत्य"

6. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

ख. परामर्श तथा निगरानी संबंधी उपाय

1. छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों और समस्याओं को पैदा करने वाले अन्य कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, छात्रों के आवास, जलपानगृह, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्ष, शौचालयों, बस-स्टैंड का औचक निरीक्षण, और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/ घटना के रोकने में प्रभावी साबित होंगे।

ग. रैगिंग मुक्त कैम्पस के विचार का सृजनात्मक रूप से प्रसार

1. विचार के प्रसार के लिए रैगिंग रोधी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां जैसे कार्यक्रम और अन्य रचनात्मक उपाय करना।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और संरक्षा ऐप रचनात्मक रूप से तैनात किए जा सकते हैं।

घ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ किए गए अन्य उपायों का उपयोग करना

1. रैगिंग संबंधित घटनाओं के कारण परेशान छात्र राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522 (24x7 टोल निःशुल्क) पर कॉल कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन helpline@antiragging.in पर रैगिंग रोधी हेल्पलाइन पर ई-मेल कर सकते हैं।
2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निगरानी एजेंसी अर्थात् अमन सत्य कचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 (केवल आपात स्थिति में) पर संपर्क करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न तरीकों के माध्यम से एक रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ विकसित की हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और दोषियों के परिप्रेक्ष्य से प्रत्येक 30 सैकेण्ड की अवधि के 05 अलग-अलग टीवीसी तैयार किए हैं।

ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/ विनियामक प्राधिकरणों/ परिषदों/ आईआईटी/ एनआईटी/ अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पोस्टरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर डिजाइन किए हैं और उनमें संवितरित किए हैं।

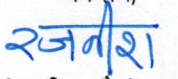
ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग की समस्या के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों/ संकायों/ आम जनता के लिए लगातार 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने अथवा संस्थान द्वारा इन विनियमों के अनुरूप रैगिंग पर लगाम लगाने हेतु पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहने पर अथवा रैगिंग की घटनाओं के अपराधियों को उपयुक्त रूप से दंडित करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के दिनांक 27 दिसंबर, 2018 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित सिफारिशों को कार्यान्वित करें और इस प्रकार एक रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करें, जोकि परिवर्तन, ज्ञानार्जन और प्रगति के प्रति उदार सहायक और निष्पक्ष संस्थागत परिवेश तैयार करने के लिए मूलतः आवश्यक है।

सादर

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

भवदीय,

(रजनीश जैन)



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-15/2009 (एआरसी) भाग-III

30 DEC 2021 23 दिसंबर, 2021

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम, 2009" अधिसूचित किया है, जो देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिफारिशें और कार्रवाई योग्य बिन्दु, जिन्हें आपके विश्वविद्यालय तथा संबद्ध/सहयुक्त सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है, निम्नवत् हैं:-

क) बुनियादी उपाय:-

1. रैगिंग रोधी समिति तथा रैगिंग रोधी दस्ते का गठन एवं रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न मीडिया के माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्था की विवरणिका एवं सूचना पुस्तिकाओं में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।
3. विद्यार्थियों के सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित नामांकन-विवरणिकाओं, सूचना-पुस्तिकाओं, पत्रकों इत्यादि के कागजी प्रति के बजाय उनकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रकाशित की जाए तथा उनमें रैगिंग रोधी निर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन को भी समाहित किए जाएँ।
4. रैगिंग रोधी समिति तथा इसके नोडल अधिकारियों के पूरे पते और उनके संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अद्यतन किया जाए।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और इसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा एक ऑनलाइन संकल्प पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है:-
"3. (i) रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, नृजातीयता, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), सेक्सुअल ओरिएंटेशन, भेष, राष्ट्रियता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी छात्र (नए या अन्यथा) पर लक्षित या शारीरिक या मानसिक शोषण (दादागिरी और बहिष्करण सहित) का कोई भी कृत्य।"
7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाना।

ख) परामर्श तथा निगरानी के उपाय:-

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और परेशानी करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंड इत्यादि का औचक निरीक्षण और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/घटना को रोकने में प्रभावी हैं, किए जाएँ।

ग) रैगिंग मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:-

1. रैगिंग रोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और इस विचार को फैलाने के लिए कोई भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा एवं संरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से प्रयोग में लाया जाए।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य उपायों का उपयोग करना:-


1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण संकट में फंसे विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग रोधी वेबसाइट helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in एवं www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निगरानी एजेंसी अमन सत्य काचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 पर (केवल आपात स्थिति में) संपर्क करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न माध्यमों से रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और आयोग ने रैगिंग रोधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संसाधन विकसित किए हैं जो आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।
 - (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषियों के परिप्रेक्ष्य से 30 सेकंड के अलग-अलग 05 टी.वी.सी विकसित किया है।
 - (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों/विनियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी/अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच वितरित किया है।
 - (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों/शिक्षकों/आम जनता के लिए 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का उल्लंघन या इन विनियमों के अनुसार रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में संस्थान की विफलता या रैगिंग की घटनाओं के दोषियों को उपयुक्त रूप से दण्डित करने में विफलता की स्थिति में उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र सं. 3-2/2021 (एआरसी) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के अनुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दायर करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें और अपनी वेबसाइट और परिसर के मत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास में अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के रैगिंग रोधी के नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध/सहयुक्त सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय,


(रजनीश जेन)

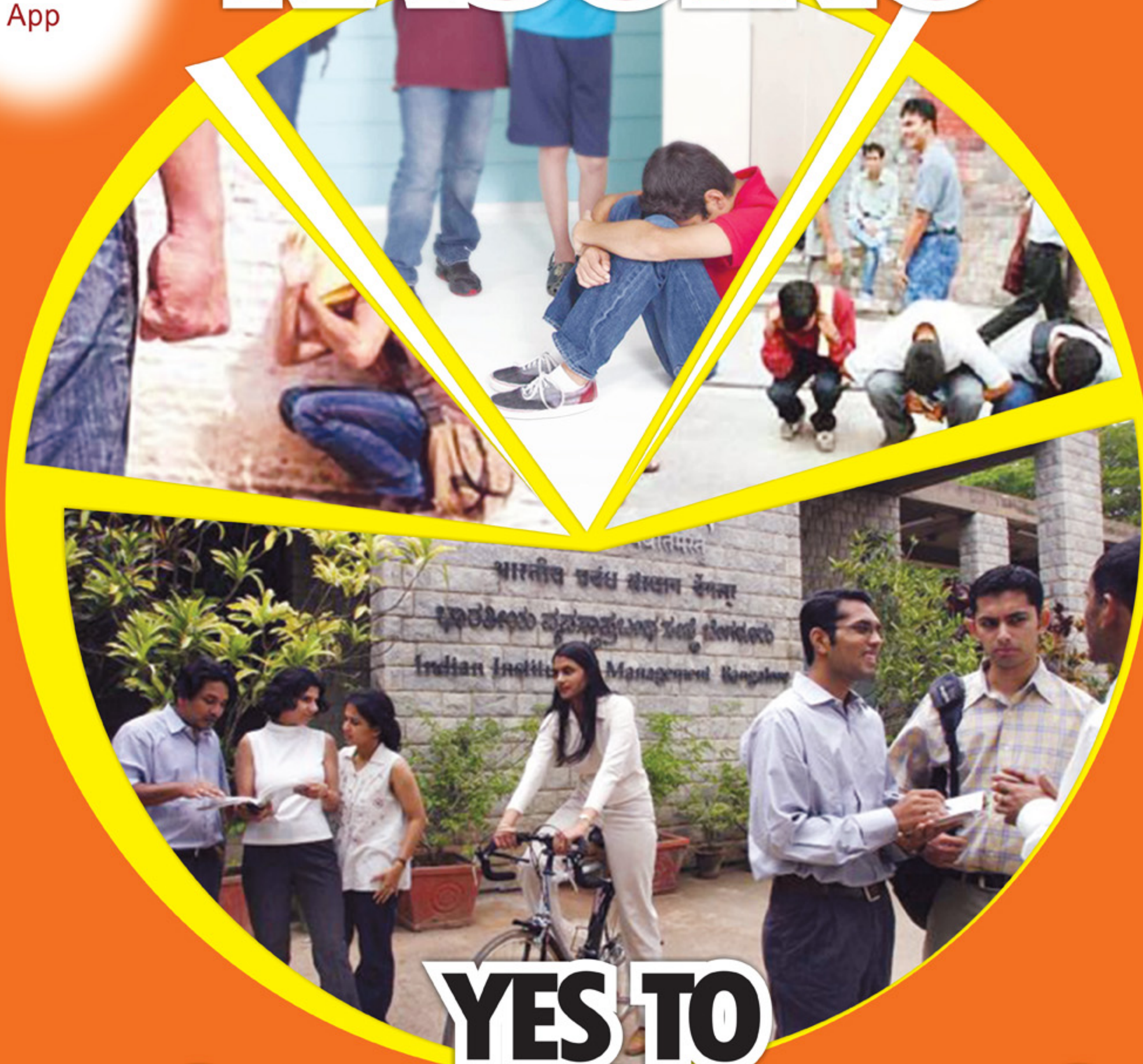
सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

Download

**ANTI
RAGGING**

App

SAY NO TO RAGGING



YES TO JOYFUL CAMPUS

What is Ragging?

Any Act Resulting in:

- Mental/physical/sexual Abuse
- Verbal Abuse
- Indecent Behaviour
- Criminal Intimidation/wrongful Restraint
- Undermining Human Dignity
- Financial Exploitation/extortion
- Use Of Force

A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:

- Cancellation of admission.
- Suspension from attending classes.
- Withholding/withdrawing Scholarship/Fellowship and other benefits.
- Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- Withholding results.
- Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament or youth festival etc.
- **Collective punishment** : when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on potential ragger.



Immediately call
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 toll free)
or send an e-mail to helpline@antiragging.in



MHRD

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

**Foolishly I ragged
& got suspended**

**Will I get
prosecuted?**

**What about my
Job prospects?**



Download

**ANTI
RAGGING**

App

MY FUTURE IS A BIG



Remember RAGGING is for LOSERS

Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations.
Are You Being Ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline- 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)
Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in



MHRD

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all



**BEFORE YOU EVEN
THINK OF RAGGING**

Download

**ANTI
RAGGING**

App



THINK OF

Humiliation

Suspension

Ruined Career

Blacklisting

Expulsion

Possible Prosecution

Don't just stand and watch. Stop Ragging! Show Character

Remember RAGGING is for LOSERS

Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations.

Are You Being Ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline- **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)**

Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in



MHRD

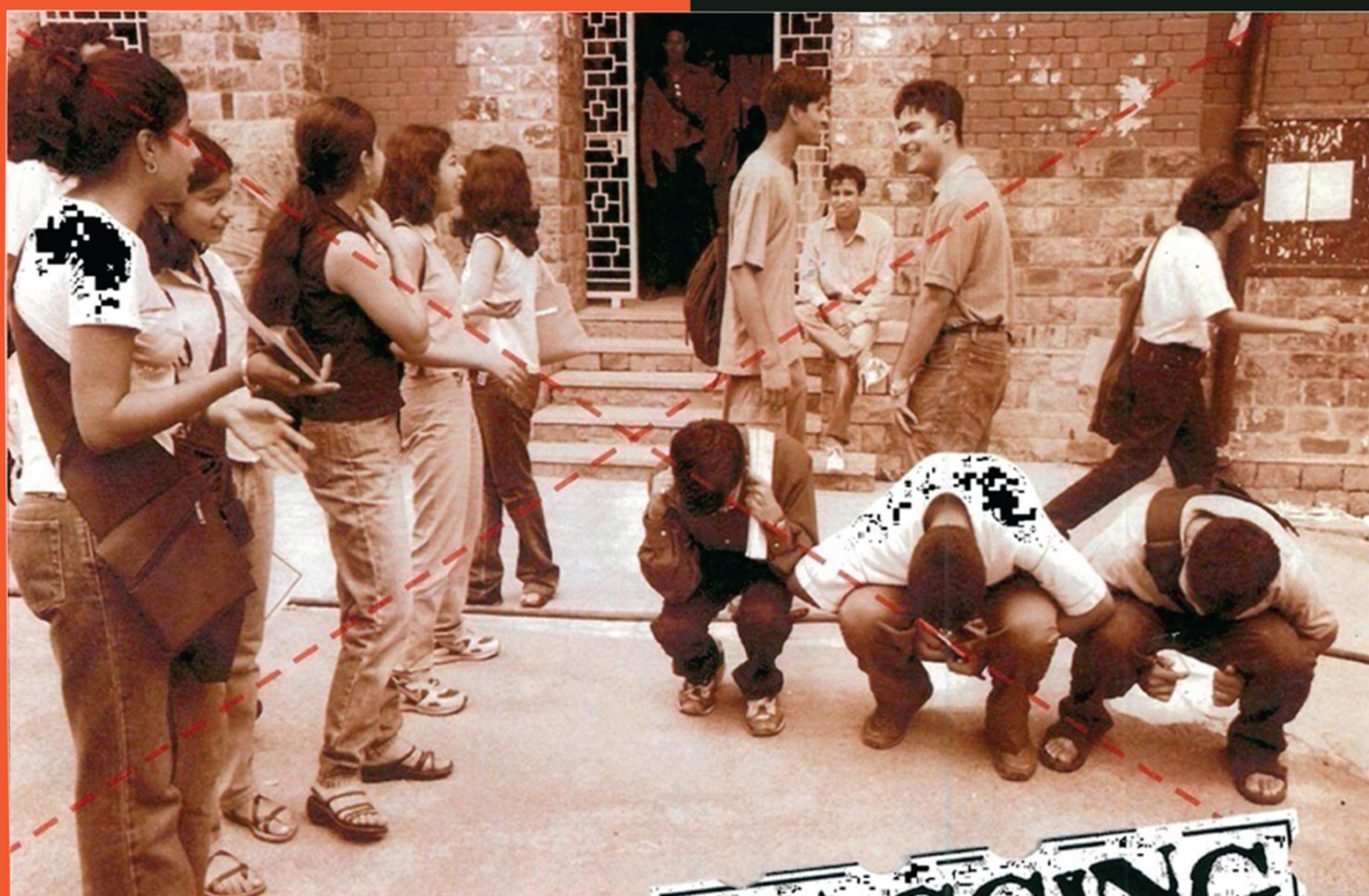
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

DON'T RAG, JUST INTERACT



Visit UGC website i.e.
www.ugc.ac.in &
www.antiragging.in to
see UGC Anti Ragging
Regulations

Are you being ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 Toll Free)
Or send an e-mail to helpline@antiragging.in

Issued in public interest by:
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Government of India

RAGGING IN ANY FORM IS PUNISHABLE

Download

**ANTI
RAGGING**

App

Join hands to make your campus ragging free



MHRD

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंगची दहशत कमी करण्यासाठी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमनांचा सारांश, 2009.

1. प्रस्तावना: दिनांक 08/05/2009 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या दृष्टिकोणातून आणि केन्द्र सरकार आणि विद्यापीठाने केलेल्या ठरावाला विचारात घेऊन रॅगिंगच्या संकटावर निर्बंध, निवारण व उच्चाटनास कार्यान्वित करण्याची अनुमती दिली गेली.
2. उद्देश्य: देशातील विद्यापीठे, डीम(मानलेली) विद्यापीठे आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्थातून रॅगिंगच्या सर्व स्वरूपांचे उच्चाटन करण्यासाठी, या नियमनांच्या अंतर्गत रॅगिंगला निर्बंधित करणे, तसेच त्यास घडू देण्यास रोखून व या संदर्भात लागू केलेल्या नियमनांतर्गत व योग्य लागू कायद्यानुसार रॅगिंगमध्ये सामील व्यक्तींना दंडित करणे.
3. रॅगिंग कशाने घटित होते: खालील पैकी एक किंवा अधिक कृत्यांनी रॅगिंग घटित होते:
 - a) कोणताही विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्यांचे शब्दांनी बोलून अथवा लिखित स्वरूपात किंवा कृतीद्वारे केलेले कोणतेही वर्तन, ज्याचा परिणाम नवीन विद्यार्थी किंवा कोणत्याही इतर विद्यार्थ्यांची थट्टा मस्करी करण्यात, किंवा उर्मटपणे वागण्यात, होतो.
 - b) कोणत्याही विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्यांद्वारे केलेली गुंडगिरी व बेशिस्तीची वागणुक जी कोणत्याही नवीन विद्यार्थी किंवा कोणत्याही इतर विद्यार्थ्यांना त्रास, हालअपेष्टा, शारिरिक, मानसिक इजा पोचवते किंवा भिती वाढवते किंवा दहशत निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते किंवा कारण होण्याची शक्यता असते.
 - c) कोणत्याही विद्यार्थ्याला अशी कृती करायला सांगणे जी तो सर्वसाधारण जिवनात करणार नाही, ज्यामुळे लाज निर्माण किंवा यातना होतील किंवा पेचात पडेल ज्याचा प्रतिकूल परिणाम नवीन विद्यार्थी किंवा कुठल्याही विद्यार्थ्यांच्या शरीर किंवा मनावर होईल.
 - d) कोणत्याही वरिष्ठ विद्यार्थ्यांद्वारे केलेले कार्य ज्याने कोणत्याही इतर विद्यार्थी किंवा नवीन विद्यार्थ्यांच्या नियमित शैक्षणिक उपक्रमात व्यत्यय येईल, त्यास रोखले जाईल किंवा भंग केले जाईल.
 - e) एका विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थ्यांच्या गटाला नेमुन दिलेले शैक्षणिक काम नवीन विद्यार्थी किंवा इतर विद्यार्थ्यांना पूर्ण करावयास सांगून त्यांची पिळवणुक करणे.
 - f) विद्यार्थ्यांद्वारे नवीन विद्यार्थी किंवा इतर विद्यार्थ्यांकडून जोर जबरदस्तीने पैसे वसूल करणे किंवा आर्थिक भार टाकणे.
 - g) कोणतेही शारीरिक दुरुपयोग, ज्यात त्याच्या सर्व भिन्न प्रकारांचा समावेश आहे: लैंगिक अपशब्द, समलिंगी मारपीट कपडे उतरविणे, जबरदस्तीने अक्षील आणि कामुक कृत्य करणे, कामुक अंगविक्षेप, करणे ज्याने आरोग्यास किंवा व्यक्तीला कोणतेही शारीरिक नुकसान किंवा इतर कोणताही धोका होणे.

- h) नवीन किंवा कोणत्याही इतर विद्यार्थ्यांना त्रास होईल भीती वाटेल असे सक्रिय किंवा निष्क्रिय स्वरूपात भाग घेऊन केलेली कोणतीही कृती किंवा अपशब्द बोलणे, ई-मेल, टपाल, द्वारे पाठविणे, सार्वजनिकरित्या अपमान करणे, ज्यातुन काम विकृत आनंद मिळवणे, किंवा दुसऱ्यांना त्रास देऊन किंवा परपिडक रोमांच मिळवणे यांचा समावेश आहे.
- i) कोणत्याही नवीन विद्यार्थ्यांवर एका विद्यार्थ्याद्वारे परपिडक आनंद मिळविण्याच्या उद्देशासह किंवा शिवाय केलेली कोणतेही कृती किंवा सामर्थ्य, प्रभुत्व किंवा श्रेष्ठता दाखविणारी कृती जी नवीन विद्यार्थी किंवा इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि आत्मविश्वासाला प्रभावित करेल.

4. रॅगिंग वर प्रतिबंध घालण्याचे उपाय: संस्था स्तरावर, विद्यापीठ स्तरावर, जिल्हा स्तरावर वगैरे अशाप्रकारचे अनेक उपाय असतात. त्यापैकी काही जे विद्यार्थ्यांस माहिती असणे महत्वाचे आहे ते खालीलप्रमाणे आहेत:

- कुठलीही संस्था कोणत्याही स्वरूपातील रॅगिंग च्या सूचीत घटनेसाठी परवानगी किंवा सूट देणार नाही; आणि सर्व संस्था, संस्थेत किंवा बाहेर, रॅगिंग चे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने या नियमनात समाविष्ट तरतूदीनुसार पण केवळ तेवढेच मर्यादीत नाही, सर्व आवश्यक आणि अपेक्षित उपाययोजना अमलात आणतील.
- सर्व संस्था, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग मध्ये सामिल आणि/किंवा त्यास प्रोत्साहन देण्यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध किंवा रॅगिंगला प्रोत्साहन देण्यातील कटकारस्थानांमध्ये सामील असणाऱ्यांविरुद्ध, या नियमनांनुसार कार्यवाही करतील.
- कुठल्याही अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश देण्याच्या उद्देशाचे कोणत्याही संस्थेकडून कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक, दृकश्रवण किंवा छापील किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे केलेल्या प्रत्येक सार्वजनिक घोषणेमध्ये सुस्पष्टपणे नमूद केलेले असावे की संस्थेमध्ये रॅगिंग पूर्णपणे निषिद्ध आहे आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करण्यामध्ये सामिल आणि/किंवा त्यास प्रोत्साहन देण्यामध्ये दोषी आढळणारे किंवा रॅगिंगला प्रोत्साहन देण्यातील कटकारस्थानांमध्ये सामील असणारे यांना नियमनांनुसार तसेच त्या वेळेपुरत्या अमलात असणाऱ्या दंडविधीच्या तरतूदीअंतर्गत शिक्षेस पात्र धरले जाईल.
- रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाइन आणि संस्थेतील सर्व महत्वाचे पदाधिकारी यांचे दुरध्वनी क्रमांक प्रवेश पुस्तिका/सुचना पुस्तिका किंवा अभ्यासक्रम पुस्तिकेमध्ये प्रकाशित केले जाईल, ज्यामध्ये संस्था प्रमुख, शिक्षक, रॅगिंग विरोधी समितिचे सदस्य, आणि रॅगिंग विरोधी पथक यांच्या दुरध्वनी क्रमांकापुरतेच मर्यादीत नाही, तर जिल्हा आणि उप विभागीय अधिकारी वर्ग, वसतीगृहाचे वार्डन आणि इतर संबंधित पदाधिकारी किंवा अधिकारी यांचाही समावेश आहे.
- विद्यार्थ्यांने यथोचित रीत्या स्वाक्षरी केलेले विहित नमून्यातील रॅगिंग विरोधी प्रतिज्ञापत्र आणि मातापिता/पालक यांनी स्वाक्षरी केलेले रॅगिंग विरोधी अन्य प्रतिज्ञापत्र प्रवेश, नामांकन किंवा नोंदणीच्या अर्जाबरोबर जोडलेले असणे आवश्यक आहे. (ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे वेबसाईट वरून डाऊनलोड करता येतील)
- रॅगिंग विरोधी हेल्पलाईनला प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही क्लेशकारक संदेशाचे प्रसारण त्याचवेळी संस्था प्रमुख, वसतीगृह अधीक्षक, विद्यापीठाशी संलग्नित संस्थेमध्ये घटना घडल्यास

संलग्न विद्यापीठाचा केंद्रीय अधिकारी, आवश्यकता भासल्यास संबंधित जिल्हा प्राधिकरण, आणि आवश्यक वाटल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे केले जाईल आणि जनतेच्या प्रभावक्षेत्रात असण्यासाठी वेबसाइट वर टाकले जाईल आणि त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमे आणि नागरीकांना ते पाहता येईल.

- रॅगिंग विरोधी पथकाची शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर किंवा रॅगिंग च्या नोंदवल्या गेलेल्या कोणत्याही घटनेची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर, ही बाब दंडविधीअंतर्गत हाताळण्याबाबत संस्था प्रमुख ताबडतोब हे निश्चित करेल, आणि असे करावयाचे झाल्यास, तो स्वतः किंवा त्याच्या वतीने हे कार्य करण्यासाठी त्याने अधिकृतपणे नेमून दिलेल्या समितीच्या सदस्यांद्वारे, अशाप्रकारची माहिती किंवा शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर चौविस तासांच्या आत, पोलीस आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसह, योग्य दंडविधी तरतूदीअंतर्गत, प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी पाऊल उचलेल.
- आयोग, विद्यार्थी व त्याच्या/तीच्या मातापिता/पालक यांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून यथोचित डेटा बेस राखेल आणि संस्था, एकतर स्वतः किंवा तीने नेमून दिलेल्या एजन्सीमार्फत तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संग्रहित करेल; आणि अशाप्रकारचा डेटा बेस प्राप्त झालेल्या रॅगिंग च्या तक्रारी, आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाही च्या स्थितीची नोंद म्हणून कार्य करेल.
- आयोग कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य किंवा कोणत्याही संस्थेचे सहाय्यक अनुदान यांच्याबाबत विशिष्ट अटीचा समावेश उपयोजन प्रमाणपत्रामध्ये कोणत्याही साधारण किंवा विशिष्ट योजनेअंतर्गत करेल, जी संस्थेने रॅगिंग विरोधी उपायांसह तयार केली असेल.
- संस्थेमधील कोणत्याही रॅगिंग च्या घटनेचा प्रतिकूल परिणाम राष्ट्रीय मूल्यनिर्धारण आणि अधिस्वीकृती परिषद किंवा कोणत्याही अन्य अधिकृत अधिस्वीकृती एजन्सी कडून अधिस्वीकृती, क्रमांकन किंवा श्रेणीकरणाच्या उद्देशाने मूल्यांकन करतांना तिच्या अधिस्वीकृती, क्रमांकन किंवा श्रेणीकरणावर होईल.
- ज्या संस्था अन्य कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या 12B कलमाअंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यास पात्र असतील, ज्यांच्याबद्दल रॅगिंग च्या कुठल्याही घटनेची नोंद नसलेला निष्कलंक अभिलेख असेल, त्या संस्थांना आयोग आर्थिक सहाय्यक अनुदानामध्ये प्राथमिकता देऊ शकेल.

5. रॅगिंग च्या घटनेमधील प्रशासकीय कार्यवाही: रॅगिंग मध्ये दोषी असलेल्या विद्यार्थ्यांस संस्था खाली दिलेल्या पद्धतीचे अनुसरण करून आणि विहित रीतीनुसार शिक्षा करेल:

- रॅगिंग विरोधी पथकाच्या शिफारसीमध्ये निश्चित केल्या गेलेल्या रॅगिंग च्या प्रत्येक घटनेच्या वास्तवावर आणि रॅगिंग च्या घटनेचा प्रकार आणि गांभीर्य यावर अवलंबून शिक्षा किंवा अन्य कोणत्याही बाबतीत संस्थेची रॅगिंग विरोधी समिती यथोचित निर्णय घेईल.
- रॅगिंग विरोधी पथकाने निश्चित केलेल्या दोषाचा प्रकार आणि गांभीर्य यावर अवलंबून, रॅगिंग विरोधी समिती, दोषी आढळणाऱ्यांना, खालीलपैकी एक किंवा जास्त प्रकारच्या शिक्षा, ठोठावू शकते, त्या म्हणजे;
 - a) वर्गामधील उपस्थिती आणि शैक्षणिक विशेषाधिकार यांपासून निलंबन.
 - b) शिष्यवृत्ती/अधिष्ठात्रवृत्ती आणि इतर लाभ रोखणे/काढून घेणे.

- c) कोणतीही चाचणी/परीक्षा किंवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी प्रतिबंध करणे.
- d) निकाल रोखणे.
- e) कोणत्याही क्षेत्रीय, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय भेट, क्रीडासत्र, युवा महोत्सव इत्यादींमध्ये संस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्यास नकार देणे.
- f) वसतीगृहातून निलंबन/बहिष्करण
- g) प्रवेश रद्द करणे.
- h) एक ते चार सत्रांच्या कालावधीकरीता संस्थेतून काढून टाकणे.
- i) विशिष्ट कालावधीकरीता संस्थेद्वारे बहिष्करण करणे आणि त्याचबरोबर कोणत्याही अन्य संस्थेमध्ये प्रवेश नाकारणे.

- रॅगिंग ची कृती करणाऱ्या किंवा त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख न पटल्यास, संस्था सामूहिक शिक्षेचा अवलंब करेल.
- रॅगिंग विरोधी समितीने दिलेल्या शिक्षेच्या आदेशाविरुद्ध अपील केली जाईल, (i) विद्यापीठाशी संलग्न किंवा त्याचा घटक भाग असलेल्या संस्थेच्या आदेशाच्या बाबतीत, विद्यापीठाच्या कुलगुरू कडे; (ii) विद्यापीठाच्या आदेशाच्या बाबतीत, त्याच्या कुलपतीकडे. (iii) संसदेच्या अधिनियमानुसार निर्माण करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महत्व असलेल्या संस्थेच्या बाबतीत, संस्थेच्या कुलगुरू किंवा कुलपतीकडे, जशी बाब असेल त्याप्रमाणे.
- रॅगिंग च्या घटनेस अटकाव करण्याकरीता सूचना देण्याच्या किंवा योग्य कार्यवाही करण्याच्या बाबतीत किंवा जे रॅगिंग च्या तक्रारींबद्दल निरुत्साही, भावनाशून्य प्रवृत्ती दर्शवतात, किंवा जे योग्य वेळेस पावले उचलण्यामध्ये अपयशी ठरतात, या नियमनांमध्ये आवश्यक असल्यास किंवा अन्य कारणाने रॅगिंग च्या घटनेस किंवा घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरीता, जेव्हा नियुक्ति प्राधिकाऱ्याच्या मतानुसार, चुकीचा संबंध विद्याशाखेच्या कोणत्याही सदस्याशी किंवा संस्थेच्या कर्मचारीवर्गाशी जोडता येण्यासारखा असेल, तर विद्याशाखेच्या सदस्याविरुद्ध किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध, अशाप्रकारच्या अधिकाऱ्यामार्फत विभागीय शिस्तभंगाची कार्यवाही संस्थेच्या विहित पद्धतीनुसार करण्यात येईल. जेव्हा अशाप्रकारच्या चुकीचा संबंध संस्था प्रमुखाशी असेल, तर अशाप्रकारच्या प्रमुखाची नियुक्ती करण्यासाठी नेमून दिलेला अधिकारी वर्ग ही विभागीय शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल, आणि ही कार्यवाही, रॅगिंगला प्रोत्साहन देणे व रॅगिंग ला प्रतिबंध घालण्याच्या बाबतीत योग्य पावले उचलणे किंवा रॅगिंग मध्ये दोषी आढळणाऱ्या विद्यार्थ्यांस शिक्षा करणे यात अपयशी ठरण्याच्या बाबतीत जी कार्यवाही केली जाऊ शकते त्याबद्दलच्या कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय असेल.

रैगिंग कशी घटित होते?

रैगिंग खालील एक किंवा अधिक कृतींनी घटित होते :-

- a) कोणताही विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्यांचे शब्दांनी बोलून अथवा लिखित स्वरूपात किंवा कृतीद्वारे केलेले कोणतेही वर्तन, ज्याचा परिणाम नवीन विद्यार्थी किंवा कोणत्याही इतर विद्यार्थ्यांची थट्टा मस्करी करण्यात, किंवा उर्मटपणे वागण्यात, होतो.
- b) कोणत्याही विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्यांद्वारे केलेली गुंडगिरी व बेशिस्तीची वागणुक जी कोणत्याही नवीन विद्यार्थी किंवा कोणत्याही इतर विद्यार्थ्यांना त्रास, हालअपेष्टा, शारिरिक, मानसिक इजा पोचवते किंवा भीती वाढवते किंवा दहशत निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते किंवा कारण होण्याची शक्यता असते.
- c) कोणत्याही विद्यार्थ्याला अशी कृती करायला सांगणे जी तो सर्वसाधारण जिवनात करणार नाही, ज्यामुळे लाज निर्माण किंवा यातना होतील किंवा पेचात पडेल ज्याचा प्रतिकूल परिणाम नवीन विद्यार्थी किंवा कुठल्याही विद्यार्थ्यांच्या शरीर किंवा मनावर होईल.
- d) कोणत्याही वरिष्ठ विद्यार्थ्यांद्वारे केलेले कार्य ज्याने कोणत्याही इतर विद्यार्थी किंवा नवीन विद्यार्थ्यांच्या नियमित शैक्षणिक उपक्रमात व्यत्यय येईल, त्यास रोखले जाईल किंवा भंग केले जाईल.
- e) एका विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थ्यांच्या गटाला नेमुन दिलेले शैक्षणिक काम नवीन विद्यार्थी किंवा इतर विद्यार्थ्यांना पूर्ण करावयास सांगून त्यांची पिळवणुक करणे.
- f) विद्यार्थ्यांद्वारे नवीन विद्यार्थी किंवा इतर विद्यार्थ्यांकडून जोर जबरदस्तीने पैसे वसूल करणे किंवा आर्थिक भार टाकणे.
- g) कोणतेही शारीरिक दुरुपयोग, ज्यात त्याच्या सर्व भिन्न प्रकारांचा समावेश आहे: लैंगिक अपशब्द, समलिंगी मारपीट कपडे उतरविणे, जबरदस्तीने अक्षील आणि कामुक कृत्य करणे, कामुक अंगविक्षेप, करणे ज्याने आरोग्यास किंवा व्यक्तीला कोणतेही शारीरिक नुकसान किंवा इतर कोणताही धोका होणे.
- h) नवीन किंवा कोणत्याही इतर विद्यार्थ्यांना त्रास होईल भीती वाटेल असे सक्रिय किंवा निष्क्रिय स्वरूपात भाग घेऊन केलेली कोणतीही कृती किंवा अपशब्द बोलणे, ई मेल, टपाल, द्वारे पाठविणे, सार्वजनिकरित्या अपमान करणे, ज्यातुन काम विकृत आनंद मिळवणे, किंवा दुस यांना त्रास देऊन किंवा परपिडक रोमांच मिळवणे यांचा समावेश आहे.

- i) कोणत्याही नवीन विद्यार्थ्यांवर एका विद्यार्थ्याद्वारे परपिडक आनंद मिळविण्याच्या उद्देशासह किंवा शिवाय केलेली कोणतेही कृती किंवा सामर्थ्य, प्रभुत्व किंवा श्रेष्ठता दाखविणारी कृती जी नवीन विद्यार्थी किंवा इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि आत्मविश्वासाला प्रभावित करेल.